

राज्यपाल ने सलूंबर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली

क्षेत्रीय विकास एवं सामुदायिक उत्थान की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश

राज्यपाल ने कहा, पात्र व्यक्ति को समय पर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो

जयपुर/सलूंबर, 27 मई। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को सलूंबर कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की अद्यतन प्रगति तथा प्राप्त उपलब्धियों पर विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अधिकारियों को पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने भौगोलिक परिस्थितियों एवं संसाधनों की कमी से प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार के लिए योजना एवं कार्यक्रम, स्थानीय नागरिकों के पलायन को रोके जाने के लिए किए जा रहे प्रयास सहित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की।

राज्यपाल ने इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उद्यान विभाग की योजनाएं, शिक्षा विभाग, टीकाकरण, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पशुपालन विभाग, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, वृक्षारोपण सहित केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं में लक्ष्यों की समय पर उपलब्धि हासिल कर जरूरतमंदों को राहत प्रदान करें।

राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने कहा कि राष्ट्र और समाज की प्रगति के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास हो कि हर वर्ग के बालक-बालिका को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले। राज्यपाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना एवं छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए पेंशन एवं छात्रवृत्ति राशि का समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक ग्राम में नल व विद्युत कनेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करने और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशील रहकर केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करावे ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ सुगमता से मिले।





